Administrations have also been requested to appoint these authorities and necessary action has been/is being taken by them.]

बिहार में सार्वजनिक टेलीफोन करने के कार्यालय

275. **डा० रामकृपाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना डिवीजन में किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) इन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के सम्बन्ध में जनता द्वारा की गई मांग कब से सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) इन सार्वजनिक टेलीफोनों को लगाये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†[**Public call offices in Bihar**

275. DR. RAMKRIPAL SINHA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the names of places in the Patna Division where public call offices are proposed to be installed;

(b) since when the public demand for the installation of public telephones at these places has been under Government's consideration; and

(c) what are the reasons for delay in the installation of these public call telephones?]

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) विभाग का प्रस्ताव है कि चालू वर्ष 1976–77 के दौरान पटना जिले के (i) कमला-गोपालपुर; नेवादा जिले के (ii) सिरडला, गया जिले के (iii) मोहनपुर; (iv) परैया और (v) गया जिले के नागला किंजर गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिए जाएं ।

(ख) और (ग) कमला-गोपालपुर में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की जांच शुरू में दिसम्बर, 1971 में की गई थी किन्तु अलाभकर होने के कारण यह प्रस्ताव उस समय छोड़ दिया गया था । नीति में परिवर्तन हो जाने पर उसी के आधार पर इस प्रस्ताव की पुनः जांच की गई और 16–9–75 को इसे मंजूरी दे दी गई थी । वर्ष 1975-76 में जब विभाग ने सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के पात्र श्रेणीगत स्थानों के मामलों पर पुनर्विचार किया तो विभाग की ओर से अन्य स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव किये गये हैं ।

†[THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (DR. SHANKER DAYAL SHARMA): (a) The Department has proposed Public Call Offices at (i) Kamala-Gopalpur in Patna District; (ii) Sirdalla in Nawadah District; (iii) Mohanpur; (iv) Paraiya and (v) Nagla Kinjor in Gaya District to be installed during the current year 1976-77.

(b) and (c) The proposal for Kamla Gopalpur was originally examined in December, 1971 and dropped, being unremunerative. The proposal was reviewed in the light of a revision in the policy and sanctioned on 16-9-1975.

At other places, the proposals have been made on the initiative of the Department when reviewing cases of eligible category stations for P.C.Os. in 1975 and 1976?]

चासनाला कोयला खान दुर्घटना से संबंधित न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन

276. **डा० रामकृपाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री 28 मई, 1976 को राज्य सभा में

† [ ] English translation.